



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 कार्तिक 1931 (श10)

(सं0 पटना 584)

पटना, सोमवार, 16 नवम्बर 2009

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

17 जुलाई 2009

सं0 7/एम0 ई0-301-04/96-2781—भारत संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल वाणिज्य-कर विभाग के क्षेत्रीय स्थापना के अंकेक्षकों की भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—

अध्याय-1

- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।—(क) यह नियमावली बिहार वाणिज्य-कर विभाग क्षेत्रीय अंकेक्षक संवर्ग नियमावली, 2009 कही जा सकेगी।
 - इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - यह तुरत प्रवृत्त होगी।
- परिभाषाएँ ।— इस नियमावली में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-
 - 'विभाग' से अभिप्रेत है वाणिज्य-कर विभाग ;
 - 'संवर्ग' से अभिप्रेत है प्रमण्डल के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत अंकेक्षक संवर्ग ;
 - 'नियुक्ति पदाधिकारी' से अभिप्रेत है वाणिज्य-कर आयुक्त; तथा
 - 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग।
- संवर्ग का गठन ।— (1) यह संवर्ग राज्यस्तरीय होगा तथा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा।
 - जो कर्मी वर्तमान में विभाग के प्रमण्डल एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में अंकेक्षक के पद पर नियुक्त एवं कार्यरत हैं, स्वतः इस सम्वर्ग में शामिल समझे जायेंगे।
 - विभिन्न कोटि के अंकेक्षकों की संख्या का आकलन राज्य सरकार द्वारा उनके स्वीकृत बल के आधार पर होगा।
 - अंकेक्षकों के स्वीकृत बल की संख्या राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर बढ़ाई या घटाई जा सकेगी।

(5) अंकेक्षक संवर्ग के पद-सोपान निम्नलिखित रीति से विहित किए जायेंगे :-

क्रमांक	ग्रेड	वेतनमान	स्तर
(i)	अंकेक्षक	4500-125-7000	मूल कोटि
(ii)	अंकेक्षक वर्ग - II	5500-175-9000	प्रोन्नति का प्रथम स्तर
(iii)	अंकेक्षक वर्ग - I	6500-200-10500	प्रोन्नति का द्वितीय स्तर

4. नियुक्ति की प्रक्रिया । - (1) अंकेक्षक संवर्ग के पद पर सीधी भर्ती की जायेगी।

(2) अंकेक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण स्नातक(गणित के साथ) अथवा वाणिज्य स्नातक होगी।

(3) न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार(कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।

(4) नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल तक गणना करके विनिश्चित रिक्तियों के आधार पर 30 अप्रैल तक आयोग को अधियाचना भेज दी जायेगी।

(5) आयोग दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा और अभ्यर्थियों के द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में न्यूनतम अर्हक प्राप्तांक के आधार पर एक मेधा सूची तैयार करेगा तथा अपनी अनुशंसा नियुक्ति पदाधिकारी को भेजेगा।

(6) प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन हेतु पाठ्यक्रम का विनिश्चय आयोग के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

5. परिवीक्षा अवधि । - नियुक्ति के पश्चात परीक्ष्यमान अवधि 2 वर्षों की होगी। उक्त अवधि में सेवा एवं आचार संतोषप्रद नहीं होने पर परीक्ष्यमान अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी और विस्तारित परीक्ष्यमान अवधि में भी सेवा एवं आचार संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर वैसे कर्मों को सेवामुक्त किया जा सकेगा।

6. प्रशिक्षण । - (i) संवर्ग के सदस्यों को परीक्ष्यमान अवधि में नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी।

(ii) संवर्ग के सदस्यों के लिए समय-समय पर अल्पावधि के रिक्रेशर की व्यवस्था भी आवश्यकतानुसार की जा सकेगी।

7. सम्पुष्टि । - (i) संवर्ग में नियुक्त सदस्य संतोषप्रद रूप से परीक्ष्यमान अवधि एवं आवश्यक प्रशिक्षण पूरा करने पर संवर्ग में सम्पुष्टि किये जा सकेंगे।

8. प्रोन्नति । - (1) संवर्ग में सम्पुष्टि अंकेक्षकों की अंकेक्षक ग्रेड-II एवं अंकेक्षक ग्रेड-II से अंकेक्षक ग्रेड-I में प्रोन्नति वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर विचारणीय होगी।

(2) राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग), द्वारा समय-समय पर विनिश्चित कालावधि पूरा करने पर एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में प्रोन्नति विचारणीय होगी।

(3) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन निम्नानुसार किया जायेगा:-

(i) वाणिज्य-कर आयुक्त-अध्यक्ष

(ii) वित्त विभाग के उपसचिव स्तर से अन्यून पदाधिकारी- सदस्य

(iii) वाणिज्य-कर विभाग के संबंधित स्थापना के प्रभारी पदाधिकारी - सदस्य

(iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनुसचित जाति/जन-जाति के उप-सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी - सदस्य

9. आरक्षण । - राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आरक्षण नीति एवं रोस्टर का नियुक्ति एवं प्रोन्नति में दृढ़ता से अनुपालन किया जायेगा।

10. कठिनाई का निराकरण । - इस नियमावली के किसी भी नियम को लागू करने में यदि कठिनाई हो तो राज्य सरकार ऐसी कठिनाई का निराकरण राजपत्र में प्रकाशित समुचित आदेश से कर सकेगी।

11. इस नियमावली के नियमों की व्याख्या करने के लिए विभाग सक्षम होगा।

12. जिन विषयों या बिन्दुओं का प्रावधान इस नियमावली में नहीं किया गया है, उसके संबंध में राज्य सरकार के कर्मियों के लिए तत्समय प्रवृत्त नियम/अनुदेश लागू होंगे।

13. निरसन । - इस नियमावली के प्रवृत्त होने पर अंकेक्षकों के संबंध में पूर्व में निर्गत प्रासंगिक संकल्प/परिपत्र आदि निरसित समझे जायेंगे।

14. नियम 13 में वर्णित ऐसे निरसन के होते हुए भी इस नियमावली के लागू होने के पूर्व किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाई या निर्गत कोई आदेश अथवा अधिसूचना इस नियमावली द्वारा या इस नियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या निर्गत अथवा प्रकाशित की गई समझी जायेगी मानो यह

नियमावली उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया या ऐसा आदेश निर्गत किया गया अथवा ऐसी अधिसूचना प्रकाशित की गयी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शुभकीर्ति मजुमदार,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 17th July 2009

No.7/ME-301-04/96-2781—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to regulate the recruitment, promotion, and other service conditions of the Auditors working in the field establishment of Commercial Taxes:-

Chapter-1

1. *Short title, extent and commencement*—(1) These 'RULES' may be called Bihar Commercial Taxes Department Field Auditors Cadre Rules-2009

(2) It shall extend to whole of the State of Bihar .

(3) They shall come into force with immediate effect.

2. *Definitions*—In these rules, unless otherwise required in the context—

(a) 'Department' means the Department of Commercial Taxes.

(b) 'Cadre' means the cadre of Auditors working in different offices of Divisions.

(c) 'Appointing Authority' means Commissioner-Cum-Secretary, Department of Commercial Taxes, and

(d) 'Commission' means the Bihar State Staff Selection Commission.

3. *Constitution of the cadre*—(1) The cadre shall be State level and shall be under the administrative control of the Department of Commercial Taxes.

(2) Employees appointed and working at present on the post of Auditors in the field offices of the Divisions of the Department shall be deemed to be automatically included in this cadre.

(3) Appraisalment of number of Auditors of different categories shall be on the basis of their sanctioned strength by the State Government.

(4) Number of sanctioned strength of Auditors may be increased/decreased from time to time by the State Government .

(5) The grades of Auditors cadre shall be prescribed in the following manner:-

Sl.No.	Grade	Pay Scale	Level
(i)	Auditor	4500-125-7000	Basic Grade
(ii)	Auditor Grade- II	5500-175-9000	1 st Promotion
(iii)	Auditor Grade I	6500-200-10500	2 nd Promotion

4. *Procedure of recruitment*—(i) Direct recruitment shall be made on the post of Auditor Cadre.

(ii) The minimum educational qualification for appointment to the post of Auditor shall be second class graduate (with Mathematics) or Commerce graduate Passed from any recognized University.

(iii) The minimum age limit shall be 21 years and the maximum age shall be the age determined by the State Government (Personnel & Administrative Reforms Department) from time to time.

(iv) The requisition shall be sent by the Appointing Authority to the Commission by 30th April after calculation on the basis of vacancies determined on 1st April of every year.

(v) The Commission shall invite applications from eligible candidates by advertisement in daily newspapers and prepare a merit list of candidates obtaining minimum qualifying marks on the basis of written competitive examination and send its recommendation to the appointing authority.

(vi) The syllabus for the conduct of Competitive examination shall be determined by the State Government in consultation with the Commission.

5. *Probation Period*—The probation period after appointment shall be of two years. The probation period may be extended up to one year if the service and conduct is not found satisfactory during the period. The appointment of such personnel shall be terminated if service and conduct is not found satisfactory during the extended period of probation.

6. *Training*—(i) The appointing authority shall arrange for conduct of training schedule during the probation period for the members of the cadre

(ii) A short time Refresher Course shall be arranged for the members of this cadre as per requirement from time to time..

7. *Confirmation*—(1) The members appointed in this cadre shall be confirmed after satisfactory completion of probation and necessary training.

8. *Promotion*—(1) The confirmed Auditors in the cadre shall be promoted to Auditors grade II and from Auditors grade II to Auditors grade I on the basis of seniority cum merit recommended by the Departmental Promotion Committee..

(2) On completion of duration (Kalawadhi) determined by the Department of Personnel and Administrative Reforms, Bihar, Patna from time to time promotions will be considered from one grade to another.

(3) Departmental promotion Committee shall be constituted in the following manner:-

(i) Commercial Taxes Commissioner- Chairman

(ii) An officer of Finance Department (Not below the rank of Deputy Secretary) – Member.

(iii) An officer in charge of establishment of Commercial Taxes Department- Member

(iv) Nominated officer of scheduled Caste/Scheduled Tribe by personnel & Administrative Reforms Department- Member.

9. *Reservation*—The reservation policy and Roster as issued by the State Government from time to time in respect of appointment and promotion shall be strictly followed .

10. *Removal of Difficulty*—If any difficulty arises in Course of implementation of any provision of this Rule the State Government may issue orders by publishing it in the gazette for removal of such a difficulty.

11. The Department shall be competent for defining any provision of this Rule .

12. Rules/instruction enforced for the time being for the employees of the state shall be applicable regarding such subject and issues which have not been provided in this Rule.

13. *Repeal*—All previous relevant Resolution/Circulars etc issued in respect of Auditors shall be deemed to be repealed with the commencement of these Rules

14. Notwithstanding anything contained in rule 13 any work done or any order issued or any proceeding passed or any notification published before the commencement

of this rule shall be deemed to have been made or passed or published as if this Rule was valid on the day such work was done or such order passed or such notification published.

By order of the Governor of Bihar,

S. MAJUMDAR,

Commissioner-cum-Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 584-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>